ग्रामीण विकास में गाँधी जी के विचारों की प्रासंगिकता

डॉ० (कु०) पंकज शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
एन०ए०एस० (पी०जी०) कॉलिज मेरठ
ईमेलः dr.pankajsharma1656@gmail.com

शोएब
शोधार्थी, इतिहास विभाग
एन०ए०एस० (पी०जी०) कॉलिज मेरठ

सारांश

भारत की संस्कृति 'सनातन–पुरातन अवधारणा पर आधारित रही है। भारत गाँवों का देश है जिसकी आर्थिक–सामाजिक प्रगति का आधार कृषि है। पौराणिक संस्कृत साहित्य के मार्कण्डेय पुराण में 'ग्राम' के सन्दर्भ में उल्लेख आया है कि जहाँ कृषि क्षेत्र समूह है वह गाँव है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। विशाल ग्रामीण जनसंख्या, पर्यावरण और इसकी भौगोलिक स्थिति ने मिलकर ग्रामीण समाज एवं संस्कृति का विकास किया है। भारत की पहचान ग्रामीण संस्कृति में निहित है। इस परम्परा की विशेषता मुख्य रूप से कृषि की प्रधानता है। महात्मा गाँधी की सोच ऐसी थी कि जब तक कृषि को पूर्णरूपेण विकास का दर्जा नहीं दिया जायेगा तब तक सम्पूर्ण भारत वर्ष के विकास की परिकल्पना अधूरी होगी। आज के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण जीवन की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था को समृद्ध बनाना, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि के विषय में जागृति पैदा करना आवश्यक है। जिसे गाँधी जी ने अपने चिंतन में व्यक्त किया है।

गाँधी जी ने ग्रामीण विकास के लिए सेवाग्राम के माध्यम से एक संरचनात्मक प्रयास किया है। जिसमें पंचायती राज, सहकारी आंदोलन, खादी एवं अन्य उद्योगों का विकास, अस्पृष्यता निवारण, मौलिक एवं प्रौढशिक्षा, ग्रामों की स्वच्छता आदि कार्यक्रम चलाये। गाँधी जी ने 1935 ई0 में वर्धा आश्रम से ग्रामीण विकास हेतु 18 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। जिसमें ग्रामोद्योग, स्वदेशी, कायिक श्रम, ट्रस्टीशिप, दरिद्र नारायण की सेवा, पंचायती राज आदि महत्त्वपूर्ण कार्य है। इन कार्यक्रमों के द्वारा गाँधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त अनेक भ्रातियों, कुप्रथाओं के उत्तेजन को समाप्त किया।

मुख्य बिन्दु

ग्राम विकास, ग्रामोद्योग, स्वदेशी, श्रम

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 12.07.2024
Approved: 15.03.2024

डॉ० (कु०) पंकज शर्मा
शोएब

ग्रामीण विकास में गाँधी जी के विचारों की प्रासंगिकता

RJPP April 24-Sept.24,
Vol. XXII, No. II,

PP. 118-123
Article No. 15

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-sept-2024-vol-xxii-no2

गाँधी जी ने अपने व्यवहारिक जीवन में ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य किये। कृषि, उद्योग व सेवा आदि सभी प्रकार के कार्यों के लिए प्रभावी योजनाएँ बनायी जो गाँधी जी के ग्राम दर्शन को प्रकट करती है चूँकि ग्रामीण विकास राष्ट्र–निर्माण की कुंजी है, यह ग्रामीण समाज को पारम्परिक अलगाव से राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के साथ एकीकरण में परिवर्तित कर सकता है।[1]

गाँधी जी ने लघु एव कुटीर उद्योगों के अधिकाधिक विकास पर बल देकर भारत के लिए निर्मित अपनी आर्थिक रणनीति के लिए साधनों का सामंजस्य प्राप्त करने का प्रयास किया है। मानव संसाधन के विकास के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसलिए आज भी गाँधी जी के इस विचार को सर्वज्ञ मान्यता प्राप्त है। गाँधी जी ने भारत के ग्रामों की प्रगति हेतू छोटे गृह एवं कुटीर उद्योगों को सर्वाधिक उपयुक्त बताया।[2]

गाँवों के आर्थिक विकास की गाँधीवादी रणनीति का दूसरा आवश्यक तत्व उद्योगों का विकेन्द्रीकरण है। गाँधी जी ने न केवल लघु उद्योगों के अधिकाधिक विकास पर बल दिया बल्कि इन उद्योगों को देश के कोने–कोने में स्थापित करने पर बल दिया। गाँधी जी ने विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन केवल आर्थिक अनिवार्यता के कारण ही नहीं, प्रत्युत अन्य कई दृष्टिकोणों से भी किया है जिनमें एक मुख्य कारण गाँवों का उत्थान करना था। उनके अनुसार भारत में विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था देश में प्रजातंत्र की रचना के लिए भी आवश्यक है।

गाँधी जी के अनुसार प्रत्येक गाँव को अपनी सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। अतः विकेन्द्रीकरण का विचार आत्मनिर्भरता की विचारधारा से जुड़ा है। अंग्रेजी शासन से पहले आवश्यक कुटीर उद्योग थे जो कि स्थानीय कच्चे माल से ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकताओं के सभी सामान बनाते थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से ग्रामोद्योग का काफी ह्रास हुआ। इसलिए गाँधी जी आत्मनिर्भरता हेतु विकेन्द्रित ग्रामोद्योग का पुनः उद्धार करना चाहते थे। विकेन्द्रीकरण की अनिवार्यता पर बल देते हुए गाँधी जी ने कहा कि हमारा ध्येय लोगों को सुखी बनाना और साथ–साथ उनकी सम्पूर्ण बौद्धिक और नैतिक उन्नति सिद्ध करना है। उनका मानना था कि यह ध्येय विकेन्द्रीकरण से ही सच हो सकता है।[3]

समग्र ग्रामीण विकास की कल्पना की आधारशिला भी गाँधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में निहित है। यदि हम उन पर विचार कर उनके माध्यमों से ग्रामीण विकास की योजनाओं का कार्यक्रम चलायें तो निश्चित रूप से गाँवों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। गाँधी जी की धारणा रही है कि गाँवों की सेवा करने से ही सच्चे स्वराज की स्थापना होगी, जबकि अन्य सब प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे। गाँधी जी का स्पष्ट विचार था कि गाँव उतने ही पुराने है जितना कि भारत पुराना है, लेकिन आज शहरों का बोल–बाला है जो गाँवों की सारी धन दौलत खींच लेते हैं जिससे गाँवों का ह्रास हो रहा है। गाँवों का शोषण एक संगठित हिंसा है। भारत की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत कृषि जीवी है, लेकिन यदि उनसे उनकी मेहनत का सारा फल खुद छीन ले या दूसरों को छीन लेने दें तो यह नहीं कहा जा सकता कि हममें स्वराज की भावना काफी मात्रा में है। गाँधी जी की कल्पना थी कि भारत का गाँव ऐसा होगा कि अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा और फिर भी दूसरी जरूरतों के लिए, जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा, वह परस्पर सहयोग से काम लेगा।[4]

किसान के महत्त्व को भी गाँधी जी ने समझा व इन्हें भी अपने रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है और इनका मुख्य धंधा खेती, किसानी है। अतः किसानों की हालत सुधारने से ही गाँव एवं देश का कल्याण है। गाँधी जी का कथन किसानों को जब अपनी अहिंसक ताकत का ख्याल हो तब दुनिया की कोई हुकुमत उनके सामने टिक नहीं सकेगी। किसान संगठन की जो सफलता का रहस्य इसमे है कि किसानों की अपनी जो तकलीफे है, जिन्हे वे समझते है, उन्हें पूरा कराने के लिये दूसरे किसी भी राजनीतिक सेतु से उनके संगठन का दुरूपयोग न करने दिया जाये। गाँधी जी चाहते थे कि ऐसा विभाग खोला जाये, जिसकी देख–रेख में मजदूरों की तरह किसानों या खेतीहारों के समस्याओं को हल करने का काम किया जाये।[5]

कितनी शोचनीय स्थिति है कि किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलती एवं कारीगरों को भी काम नहीं मिलता। ये तीनों गांव उत्पादक है, इन्हीं से गाँव है, जब ये ही तबाह है तो गाँव भी तबाह हैं। अगर खेतीहर की उपज का उचित मूल्य मिलने लगे तो उसकी कमाई बढ़ेगी जिससे वह खुशी से खेती में पूँजी लगायेगा और खेती के अलावा नये धन्धे भी खोलेगा।

गाँधी जी के ग्रामीण विकास के आर्थिक ढाँचे की आधारशिला स्वदेशी और ग्रामोद्योग दोनों परस्पर सम्बन्धित है। साधारणतः स्वदेशी को काफी संकुचित अर्थ में समझा जाता है, परन्तु गाँधी जी ने स्वदेशी का काफी विस्तृत अर्थ लिया है। उन्होंने स्वदेशी की परिभाषा से यह कहा कि जो वस्तु करोड़ों भारतीयों के हितों का संवर्द्धन करती हो, भले ही उसमें लगी पूँजी और कौशल विदेशी हो, परन्तु यह पूँजी और कौशल भारतीय नियंत्रण के अधीन होना चाहिए। स्वदेशी में स्वयं की ही नहीं वरन अपने पड़ोसी की भावना भी निहित है। स्वदेशी कर्म के पालन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि विदेशी चीजों से घृणा की जाये। गाँधी जी स्वदेशी को किसी भी देश के लिए अनिवार्य मानते थे तथा सभी देशों को भी इसका पालन करना चाहिए।

ग्रामोद्योग सम्बन्धी विचार गाँधी जी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक रूप है। भारतीय परिस्थितियों को सामने रखकर उन्होंने ग्रामोद्योग का विचार देश के सामने रखा। गाँवो के अनुसार खादी का मूल उद्देश्य प्रत्येक गाँव को अपने भोजन एवं कपड़ों में स्वावलम्बी बनाना है अर्थात व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे। जो वस्तुऐ गाँव में उत्पादित होता है उनका पक्का माल भी गाँव में तैयार किया जाये। कपास गॉव में उत्पादित होती है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि कपड़ा भी गाँव में बने। किंतु ऐसा नहीं है कि गाँधी जी सदैव मिलों का विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि सूती मिल के साथ–साथ चरखे न चल सकने के लिए कोई कारण नहीं है। जिस तरह घर का रसोईघर भी चलता है और होटल भी चलता है उसी प्रकार ये दोनों साथ–साथ चल सकते है।[6]

ग्रामोद्योग योजना के पीछे भावना यह थी कि हम अपनी दैनिक आवश्यकतओं की पूर्ति गाँवों से करें और जब हम यह देखें कि कुछ आवश्यकतओं की पूर्ति गाँवों द्वारा नहीं हो सकती, तब हमें यह पता लगना चाहिए कि क्या थोड़े से यत्न तथा संगठन द्वारा ग्रामीण जन ही लाभकारी ढ़ंग से इन वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर सकते। गाँधी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था का गंभीर अध्ययन किया और

उसके बाद खादी ग्रामोद्योग का विचार देश के समक्ष प्रस्तुत किया। करोडों भारतीय रोजगार हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग का सहारा लेकर अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सकते हैं। गाँधी जी रोजगार के रूप में उन्हीं उद्योगों को अपनाने के लिए कहते हैं जिनसे व्यक्ति उतना उत्पादन कर ले जिससे उसकी आवश्यकतओं की पूर्ति आसानी से हो सके।[7]

कृषि प्रधान देश भारत में कृषक, कृषि ग्राम विकास, भूमि सुधार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। भूमि सुधार गरीबी दूर करने, कृषि के आधुनिकीकरण करने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। गाँधी जी ने फीनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म द्वारा ऐसा प्रयोग प्रारम्भ किया जिसने उनके जीवन में सूत्रधार का कार्य किया। उन्होंने राष्ट्र के सबसे व्यापक और पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रयोग आरम्भ किये। उनका कहना था कि भारत का दिग्दर्शन करना हो तो गाँवों में जाओ। उनका यह संदेश बराबर सुना जाता था– 'भारत स्वयं के गाँवों में बसा है।'' सच तो यह है कि ग्राम स्वराज्य ही उनके जीवन का लक्ष्य था। ग्राम सुधार के लिए गाँवों की पुर्नरचना को गाँधी जी आवश्यक मानते थे। उनका भूमि सुधार कृषक, कृषि भूमि, उत्पादन, समाज और देश के उत्थान से जुड़ा था।[8]

गाँधी जी के अनुसार हम एक ऊँची ग्राम सभ्यता के उत्तराधिकारी है। हमारे देश की विशालता, आबादी की अधिकता और हमारी भूमि की स्थिति तथा पर्यावरण ने मेरी राय में मानो यह तय कर दिया है कि उसकी सभ्यता ग्राम सभ्यता ही होगी। कृषि विकास के लिए जरूरी है कि अच्छे बीजों और उचित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाये, सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाये।

कृषि भूमि के क्षेत्र को बढ़ाने का मुख्य तरीका साल में दो फसलें व मिश्रित फसले उगाना है। इस नीति में जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन द्वारा सूखी जमीन में और अधिक नमी बढ़ाई जा सकती है ताकि कृषि उत्पादन को लगातार बढाया जा सके। बारानी खेती और तिलहनों तथा दालों के उत्पादन के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाये। छोटे और सीमांत किसनों की कृषि उत्पादनों से आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से लघु सिंचाई योजनाओं और ज्यादा जमीन को फसल योग्य बनाने के उपाय किये जायें। इसलिये गाँधी जी ने शहरों की अपेक्षा गाँवों को महत्त्व दिया। उनके विचार में भारत का असली रूप तो गाँवों में देखने को मिलता है। गाँवों की जो दुर्दशा थी, उससे द्रवित होकर देशवासियों के सामने ग्राम सेवा का कार्यक्रम रखा। ग्राम सुधार के लिए गाँधी जी ग्रामवासियों की शिक्षा नगरवासियों के लिए भी आवश्यक मानते थे। इसी प्रसंग में गाँधी जी ने हरिजन के 11 अप्रैल, 1948 के अंक में लिखा था ग्राम सुधार में केवल ग्रामवासियों के ही शिक्षण की बात नहीं है, शहरवासियों को भी उससे उतना ही शिक्षण लेना है।

भले ही स्वतंत्रता के बाद गाँवों में चहुँमुखी प्रगति हुई हो पर गाँधी जी ने जिन स्तम्भों पर स्वस्थ भारत की नींव डालनी चाही थी, वे अब भी कुछ सीमा तक उपेक्षित है। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा महात्मा गाँधी के विचारों को आत्मसात करते हुये गाँवों के विकास के लिए कुटीर उद्योगों और हस्तउद्योग आदि के महत्व को समझते हुये 'आत्मनिर्भर भारत' नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 2047 तक भारत के गाँवों को भी आत्मनिर्भर बनाकर विकसित देशों के समकक्ष लाना है।

संदर्भ

1. आर. के. प्रभु, महात्मा गाँधी के विचार, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ **233**.
2. एस. नारायण, रैलिवेंस आफ गाँधीयन इकोमोमिक्स, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद, 1970, पृष्ठ **20**.
3. हरिजन सेवक, 18–10–1942
4. गाँधी, गाँवों का पुनर्निर्माण, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली 2014, पृष्ठ **9**6
5. गांधी, रचनात्मक कार्यक्रम, पृष्ठ–**38–41**
6. यंग इण्डिया, 21–07,1920,
7. यंग इण्डिया, 14–10–1920
8. दीपांशु अग्रवाल, महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की सार्थकता, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ–**35**